साप्ताहिक
जागत गांव हमार
पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक
RNI-MPHIN/2015/72544
चौपाल से भोपाल तक
भोपाल, सोमवार, 05-11 अगस्त 2024 वर्ष-10, अंक-16
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित
पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

कंपनियों को सप्लाई होगा टोमैटो प्रोडक्ट, भिंड के किसान कर रहे टमाटर की खेती

खुशखबरी! किसानों को मिलेंगे अच्छे दाम चंबल में खुलेगी टमाटर की प्रोसेसिंग यूनिट

» काशीपुरा, सिरसौदा स्वसहायता समूह बना रहे टोमैटो के प्रोडक्ट

» मालनपुर यूनिट में टोमैटो कैचअप, चटनी जैसे उत्पाद होंगे तैयार

भोपाल। जागत गांव हमार

टमाटर की फसल में मंदी की मार झेल रहे चंबल के किसानों के लिए अच्छी खबर है। उनकी मदद के लिए फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की कवायद जल्द ही शुरू होने वाली है। इसमें उनकी फसल की खपत तो होगी ही साथ ही फसल के दाम भी अच्छे मिलेंगे। कृषि विभाग आत्मा योजना के तहत किसानों का समूह बनाकर कलस्टर बना रहे है। अधिकारियों का कहना है कि टमाटर उत्पादक किसानों को अभी अपनी फसल बेचने के लिए दूसरे प्रदेशों में भटकना पड़ रहा है। भिंड के अलावा शिवपुरी, दतिया, मुरैना आदि जिले के किसानों को अच्छे भाव नहीं मिल रहा। इसे देखते हुए क्लस्टर बनाकर औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में यूनिट लगाने लगाई जाएगी। इसके लिए अधिकारियों ने औद्योगिक क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग चला रहे कंपनी प्रबंधक से बात भी की है। इकाई लगाने पर कुल लागत राशि का 35 फीसदी तक और बैंक ऋण पर लगने वाले ब्याज पर 3 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।

किसानों को अच्छा दाम मिलेगा

वर्तमान में भिंड जिले में 853 हेक्टेयर में एक हजार से अधिक किसान टमाटर का उत्पादन करते हैं। कई बार किसानों को टमाटर का उचित दाम नहीं मिल पाता, जिससे लागत पूरी करनी भी मुश्किल होती है। इस वर्ष भी मंडी में टमाटर पांच से 10 रुपए प्रतिकिलो तक बिका है। प्रोसेसिंग यूनिट लगने के बाद किसानों को टमाटर का अच्छा दाम मिलेगा।

किसानों को बनाया जाएगा शेयर होल्डर

उप संचालक कृषि के मुताबिक जैविक टमाटर उत्पादन को बढ़ाने के लिए आत्मा के तहत किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही कलस्टर बनाने के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए करीब 1000 से अधिक किसानों को शेयर होल्डर बनाया जाएगा। प्लांट में होने वाले मुनाफे को शेयर होल्डर किसानों में बांटा जाएगा।

नामी कंपनियों को होगी सप्लाई

प्लांट में रोज 200 क्विंटल टमाटर से पेस्ट तैयार किया जाएगा। इस पेस्ट को कंपनी की ओर से टोमैटो सॉस व कैचअप बनाने वाली देश की नामी कंपनियों को सप्लाई किया जाएगा। वर्तमान में स्वसहायता समूहों द्वारा कैचप और अचार बनाकर भिंड-ग्वालियर के बाजार में सप्लाई किया जा रहा है। यूनिट शुरू होने से टमाटर से कई उत्पाद बन सकेंगे।

चटनी जैसे उत्पाद किए जाएंगे तैयार

जिला उद्यानिक अधिकारी तोमर के मुताबिक टमाटर को छह से आठ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व 90 प्रतिशत रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर लंबे समय तक रखा जा सकता है। टमाटर के क्षेत्र में प्रसंस्करण के द्वारा सर्वाधिक प्रचलित उत्पादों में टोमैटो केचअप, टोमैटो पल्प, टोमैटो प्यूरी, टोमैटो पाउडर, फील्ड टोमैटो, टोमैटो सूप, चटनी तैयार होगी। मालनपुर में यूनिट शुरू होने पर आसपास के जिले शिवपुरी, दतिया, मुरैना और श्योपुर के किसान भी अपना टमाटर बेच सकेंगे।

बी और सी ग्रेड के टमाटर किसानों को मंडी में ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। टमाटर प्रोसेसिंग यूनिट में इसका अच्छा दाम मिलेगा। यूनिट लगाने के लिए इस बार 1100 हेक्टेयर में टमाटर की फसल करने के लिए 1500 किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है।

जीएस तोमर, जिला उद्यानिकी विभाग अधिकारी

जिले में टमाटर उत्पादक किसानों को भाव नहीं मिल पाता। इसलिए कृषि विभाग किसानों का समूह बनाकर कलस्टर तैयार कर रहा है। मालनपुर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट चालू कराने की तैयारी है। प्लांट लगने से किसानों को मुनाफा होगा। चंबल की अलग पहचान बनेगी।

रामसुजान शर्मा, उप संचालक कृषि भिंड

अच्छा काम करने वाली समिति होगी पुरस्कृत, हेल्प डेस्क भी बनेगाः सारंग

नवाचार करने वाली सहकारी समितियों का बनेगा फेडरेशन

भोपाल। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि सहकारिता में नवाचार करने वाली समितियों का प्रदेश स्तर पर फेडरेशन बनाया जाएगा। फेडरेशन के माध्यम से उनके उत्पाद के विक्रय की संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। मंत्री नवाचार के अंतर्गत जिला नोडल अधिकारियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने सहकारिता के उत्पादों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। मंत्री ने कहा कि सहकारी समितियों का प्रदेश स्तर पर कॉम्पिटीशन होगा। इसके लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। हर साल इसका आयोजन करने के निर्देश उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि इससे अग्रणी रहने के लिए खेलभावना से आगे रहने की आदत होगी। राज्य सहकारी संघ के माध्यम से प्रदेश स्तर पर हेल्प डेस्क भी बनाई जा रही है जो तकनीकी ज्ञान के साथ विक्रय में सहायता आदि प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के विजन एवं आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सहकारिता में विभिन्न नवाचार किया जा रहे हैं। हर क्षेत्र में सहकारी आंदोलन को मजबूत करते हुए सहकारिता से स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। हर क्षेत्र की खूबी को रोजगार में बदलने का प्रयास होगा। सरकारी आंदोलन को मजबूत करके सहकारी संस्था के माध्यम से रोजगार मिल सके, इसका प्रयास जारी है। सहकारिता से समृद्धि हमारा संकल्प है। निश्चित रूप से देश में जो सहकारी आंदोलन चल रहा है, उसमें मध्य प्रदेश अव्वल रहे, इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं।

2.29 करोड़ रुपए का घोटाला आया सामने, सरकार ने दिए वसूली के आदेश

जैविक खेती में अधिकारियों ने उगाई भ्रष्टाचार की फसल

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के अनूपपुर में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। यहां कृषि विभाग के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार की फसल तैयार की है। यह मध्य प्रदेश का वही अनूपपुर जिला है, जहां पूरे देश में सबसे अधिक जैविक खेती का रकबा है। अधिकारियों ने दो करोड़ 29 लाख रुपए का घोटाला किया है। घोटाले को 2018 से 2020 के बीच अंजाम दिया गया। कृषि विभाग के अधिकारियों ने केंचुए और अन्य सामग्री में गड़बड़ी कर विभाग को चूना लगाया है। शहडोल के रहने वाले दीपक मिश्रा ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को शिकायत दी थी। उन्होंने गड़बड़ी की जांच की मांग भी की थी। जांच कराने पर शिकायत सही मिली। इसके बाद कलेक्टर ने शासन और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को जानकारी भेजी। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा।

पांच किसानों का हुआ था चयन

योजना के मुताबिक अनूपपुर जिले के पांच हजार किसानों को जैविक खाद, केंचुआ, जाल, वर्मी कंपोस्टिंग बेड आदि प्रदान करना था। इस संदर्भ में जिला खनिज निधि से छह करोड़ 93 लाख रुपए की राशि भी जारी की गई थी।

किसे-कितनी राशि आवंटित

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी परियोजना को सामग्री खरीदने की खातिर 2.29 करोड़, प्रशिक्षण और अन्य कामों के लिए 2.93 लाख रुपए का आवंटन किया गया। 1.08 करोड़ की धनराशि एक निजी कंपनी को दी गई, ताकि वह मिट्टी परीक्षण कर सके। योजना के मुताबिक हर किसान को 9770 रुपए का आवंटन किया गया था।

जांच में चौंकाने वाला सुलासा

जब जिला प्रशासन ने किसानों से जानकारी हासिल की तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। किसानों ने बताया कि केंचुआ और अन्य सामग्री विभाग ने दी ही नहीं। मिट्टी के परीक्षण में भी गड़बड़ी की गई। अब कलेक्टर ने पूरे मामले में कड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कृषि उप संचालक से 2.29 करोड़ की वसूली और विभागीय जांच करने का आदेश दिया है। साथ ही निलंबन प्रस्ताव भी भेजा है।

आर्थिक अपराध शाखा से घोटाले से जुड़ा पत्र मिला था। इसके बाद कमेटी ने मामले की जांच की। जांच में 2018 से 2020 के बीच कृषि विभाग में 2.29 करोड़ का भ्रष्टाचार मिला है। जानकारी आर्थिक अपराध शाखा रीवा और शासन को भेज दी है।

अमन वैष्णव, अपर कलेक्टर, अनूपपुर

विज्ञानिकों ने तीन जिलों के 500 से ज्यादा किसानों को जागरूक करते हुए अभियान से जोड़ा

बिना पराली जलाए फसल उगाकर निकाला प्रदूषण का हल, जबलपुर, कटनी और छिंदवाड़ा में प्रयोग सफल

जबलपुर। जागत गांव हमार

फसल कटाई के बाद खेतों का कचरा (पराली) जलाने से किसानों को रोकने के प्रयास में अब प्रशासन के साथ कृषि वैज्ञानिक भी जुट गए हैं। इसमें बीसा यानि बोरलाग इंस्टीट्यूट आफ साउथ एशिया के जबलपुर स्थित केंद्र के विज्ञानियों ने एक सफल प्रयोग किया है। विज्ञानिकों ने मध्य प्रदेश के तीन जिले, जबलपुर, कटनी और छिंदवाड़ा के 500 से ज्यादा किसानों को जागरूक करते हुए अभियान से जोड़ा। उनकी 800 एकड़ कृषि भूमि में बिना पराली जलाए और बिना जुताई किए मूंग की खेती की। हैप्पी सीडर नामक कृषि यंत्र से खेतों में सूखी पराली के बीच ही मूंग के बीज बो दिए गए। बीज डालने के बाद विज्ञानिकों व किसानों ने खेतों की लगातार निगरानी की। इस दौरान फसल को दिए जाने वाले पौष्टिक तत्व में कोई बदलाव नहीं किया। इसका परिणाम अच्छा रहा और मूंग की अच्छी फसल हुई। बीसा के विज्ञानिक डॉ. रवि गोपाल सिंह बताते हैं कि खेतों में फसल की कटाई के बाद पराली जलाने के मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है। उन्होंने बताया कि जिस तरह प्रदेश में पराली जलाने का क्रम बढ़ा है उस हिसाब से यह पंजाब को पीछे छोड़ देगा। पर्यावरण और भूमि संरक्षण के उद्देश्य से बीसा ने किसानों को उनके खेतों में जाकर लाइव डेमो दिया और पराली जलाने और न जलाने, दोनों के फायदे-नुकसान बताए। इसके बाद गेहूं की कटाई के चंद घंटों बाद पराली जलाए बिना ही खेतों में मूंग लगा दी। 72 दिन में तैयार होने वाली मूंग की फसल की कटाई हो चुकी है। उत्पादन भी अच्छा मिला है।

आर्गनिक कार्बन उपयोगी

बीसा इंस्टीट्यूट के बाद विज्ञानिक डॉ. महेश मस्के ने बताया कि पराली में आर्गनिक कार्बन होता है, जो ठीक इंसानों के हिमोग्लोबिन की तरह काम करता है। यह आर्गनिक कार्बन मिट्टी की ताकत बढ़ाता और उसे स्वस्थ रखता है, लेकिन इसे जला देने से यह नष्ट हो जाता है। उन्होंने बताया कि जहां तक मूंग लगाने की बात है तो गेहूं और चावल आदि जिस मिट्टी से पौषक तत्व लेते हैं, लेकिन मूंग देती है। इसमें मौजूद नाइट्रोजन से मिट्टी उपजाऊ होती है।

अन्य प्रदेश में रखेंगे परिणाम

बीसा इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ विज्ञानिक डॉ. रवि गोपाल सिंह ने बताया कि इस प्रयोग ने न केवल मिट्टी के नुकसान को कम किया, बल्कि खेती की लागत भी कम हुई। किसान, किताब से ज्यादा प्रयोग करके सीखता है, इसलिए हमने उनके खेत में ही यह प्रयोग किया जो सफल रहा है। इस परिणाम को देश के अन्य प्रदेश के किसानों के सामने रखा जाएगा।

बिना पराली जलाए की सफल खेती

कटनी के निकट बोहरीबंद के किसान सत्येंद्र कुमार के खेत में यह प्रयोग किया गया। वह बताते हैं कि शुरू में तो उन्हें अटपटा लगा। बार-बार यह सवाल मन में उठता रहा कि बिना पराली जलाए, दूसरी फसल कैसे पनपेगी, पर बीसा के विज्ञानिक डॉ. महेश ने हमारे खेत में बिना पराली जलाए मूंग लगाई। आज फसल लहलहा रही है। इसी गांव के किसान छलकन सिंह ने बताया कि बिना पराली जलाए मूंग की अच्छी उपज ली जा सकती है।

कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने कृषि मंत्री कंषाना को लिखा पत्र

बीज उत्पादक कंपनियां बोगस प्रमाण पत्रों के सहारे कर रहीं खेला

प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा कि बीज खरीदी और प्रमाणीकरण में कोई गडबड़ी नहीं हुई है, के तथ्यहीन बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जहां-जहां गड़बड़ी हुई है उसके प्रमाणित तथ्य मौजूद है, पत्र के माध्यम से कृषि मंत्री के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि प्रदेश कांगेस द्वारा इस मामले को लेकर एक पत्रकार वार्ता कर मामला उठाया था। गड़बड़ी की प्रमाणित प्रति पत्र के माध्यम से कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना के अव-लोकनार्थ भेजी गई है।

भोपाल। जागत गांव हमार

नायक ने कहा कि मंत्री द्वारा जानकर भी अनजान बनना यह आत्म प्रवंचना है, खुद के द्वारा खुद को ठगने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि बीज उत्पादक कंपनियां बाजारों में निम्न गुणवत्ता के बीज खरीद कर, बोगस प्रमाण पत्रों का उपयोग कर शासन के माध्यम से किसानों को वितरित कर हजारों करोड़ का खेल कर रही हैं। इस खेल में लाखो कृषकों का उत्पादन घट गया और लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कंपनियों ने घटिया क्वालिटी के अप्रमाणित बीज खरीद कर राज्य शासन के सरंक्षण में लाखों किसानों को दे दिया और उसी का परिणाम है कि प्रदेश में कई फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में कमी आई। उदाहरण है कि राज्य बीज एवम फार्म विकास निगम में 2018-19 में प्रति हेक्टेयर उत्पादन 12.12 क्विंटल था जो 2022-23 में घटकर 10.49 क्विंटल रह गया।

बोगस बीज का बड़ा मामला ग्वालियर संभाग और उज्जैन संभाग में देखा गया है। धोखाधड़ी को लेकर ईओडब्लू में कम्पनी के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किया गया। पूरे प्रदेश में बोगस बीज को लेकर प्रमाणित शिकायतें सामने आई हैं।

बीज ग्राम योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में 26 करोड़, 33 करोड़ तथा 42 करोड़ रुपए व्यय किए गए तथा प्रजनक बीज उत्पादक संस्थाओं को करोड़ों का अनुदान दिया गया। पैसा कहां व्यय किया गया, अनुदान किन संस्थाओं को दिया गया लाभान्वित किसे किया गया, इसका कोई हिसाब नहीं हैं।

सारा कार्य बोगस, कागजों पर चल रहा फ्रॉड

सारा कार्य बोगस, कागजों पर, और फ्रॉड हैं। बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा खरीफ की फसलो में बोगस बीज प्रमाणीकरण का खेल जमकर किया गया। पिछले तीन वर्षों में 60 से 80 हजार नमूनों का परीक्षण किया 20 प्रतिशत से अधिक नमूने अमानक पाए गए लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। 8 प्रमुख बीज उत्पादक संस्थाओं ने पिछले 15 वर्ष में जिन फसलों का जितना बीज जिस गुणवत्ता का उपलब्ध कराया, वह सारा बोगस हैं, और हजारो करोड़ रुपए मानक बीज के नाम पर डकार लिए गए। शासन स्तर पर बोगस बीच के प्रमाणीकरण से प्रदेश में अधिकांश फसलों के पिछले 15 वर्षों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में चिंताजनक कमी हुई है। किसान की आर्थिक स्थिति दयनीय बनी हुई है। वे कर्जदार बने हुए हैं। यह हजारों हजार अन्नदाताओं के साथ विश्वासघात है। इस पूरे भ्रष्टाचार का एक-एक फलक कृषि मंत्री को आईना दिखाएगा।

एक ड्रोन की कीमत फिलहाल 5 से 15 लाख रुपए, संचालन से पहले पायलट लाइसेंस अनिवार्य

अब ड्रोन भैया भी कृषि को देंगे स्वरोजगार का संबल

खेतों में अब ड्रोन दीदी के बाद ड्रोन वाले भैया भी नजर आएंगे। ड्रोन का प्रशिक्षण लेकर युवाओं को निःशुल्क प्रदर्शन करके दिखा रहे जबलपुर के पीयूष का कहना है कि वह स्वयं और अन्य युवाओं को भविष्य में आत्मनिर्भर होने की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। खेती को

तकनीक से जोड़ने से समय और पैसों दोनों की बचत होगी। दस ड्रोन लेकर वे जिले के विभिन्न गांवों में पहुंचते हैं और किसानों-युवाओं को इसके फायदे समझाते हैं। वर्तमान में एक ड्रोन की कीमत फिलहाल 5 से 15 लाख रुपए तक है। ड्रोन संचालन से पहले पायलट लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

भोपाल। जागत गांव हमार

भोपाल और इंदौर स्थित प्रशिक्षण केंद्र से सात दिन का प्रशिक्षण लेने के बाद शासन की योजना का लाभ और ड्रोन में सब्सिडी भी मिल जाती है। 30 हजार के शुल्क वाले इस प्रशिक्षण पर सब्सिडी देकर फिलहाल 18 हजार लिए जा रहे हैं। अन्नदाता के हाथ को मजबूत करने के साथ ही समय की बचत का मंत्र लिए यह आधुनिक ड्रोन आठ मिनट में एक एकड़ कृषि भूमि में कीटनाशक का छिड़काव करने में सक्षम हैं।

यह तकनीक युवाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही आर्थिक रूप से समृद्ध भी बनाएगी। कृषि विभाग ने भी जबलपुर, सतना, रीवा, सागर समेत अन्य संभागों में ड्रोन को कृषि कार्य से जोड़ने के लिए पहल की है। सब्सिडी के जरिए ड्रोन खरीद के फायदे भी बताए जा रहे हैं। पहले चरण में पंद्रह से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन जिले में पहुंच गए हैं।

घंटों का काम मिनटों में होगा: खेती में नवोन्मेष व तकनीक के साथ बढ़ रहे इन कदमों से अन्नदाता की बड़ी समस्या काफी हद तक दूर होगी। यूरिया, कीटनाशक या अन्य तरल पदार्थ के छिड़कने स्वयं खेतों का रुख करना पड़ता था या फिर मजदूरों का सहारा लेना पड़ता था। नई तकनीक से लैस ये ड्रोन आठ मिनट में एक एकड़ कृषि भूमि में कीटनाशक का छिड़काव करने में सक्षम हैं। पहले यह कार्य चार से पांच घंटे में होता था उसमें भी एक जैसा छिड़काव संभव नहीं हो पाता था। पांच से 25 लीटर तक कीटनाशक भरकर उड़ने की क्षमता वाले ड्रोन खेतों में कार्य करने के लिए उपलब्ध होने लगे हैं।

विदेशों में तकनीक कारगर

कृषि अभियांत्रिकी विभाग केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं के अंतर्गत कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्यरत है। ड्रोन खरीदने के लिए निश्चित कंपनियों के साथ सरकार ने करार किया है। भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी ग्रामीण अंचलों में ड्रोन से किसानों को रूबरू कराया जा चुका है। यह ड्रोन कीटनाशक भरकर 10 से 100 फिट ऊपर तक उड़ने में सक्षम होते हैं। इसे जहां से इस उड़ाया जाएगा वहीं वापस भी आ जाएगा। बैटरी खत्म होने पर भी यह क्षतिग्रस्त नहीं होगा और सुरक्षित लैंड भी करेगा। ड्रोन जीपीएस, टाइमर सहित कई आधुनिक तकनीकों से लैस है।

किसानों को निःशुल्क डेमो

जबलपुर के पिपरिया, खमरिया निवासी 25 वर्षीय निखिल साहू ने जबलपुर संभाग में प्रथम ड्रोन हाईटेक हब की स्थापना की है। पिपरिया स्थित श्रीराम इंटरप्राइजेज ने कीटनाशक के छिड़काव के लिए 10 एग्रीकल्चर ड्रोन लिए हैं। निखिल गांवों में पहुंचकर निःशुल्क डेमो भी दे रहे हैं। एक ड्रोन से दिनभर में लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में छिड़काव किया जा सकता है।

जिला	ड्रोन संख्या
जबलपुर	10 ड्रोन
छिंदवाड़ा	02 ड्रोन
सिवनी	02 ड्रोन
नरसिंहपुर	01 ड्रोन

- किसानों के लिए ड्रोन काफी फायदेमंद हैं। ड्रोन के प्रयोग से समय की बचत के साथ पैसों की बचत भी होती है। ड्रोन खरीदने में शासन से अनुदान भी मिलता है। किसानों को आगे आना चाहिए और योजना का लाभ लेना चाहिए।
वीके सोनवानी, कृषि यंत्री, जबलपुर संभाग

- सिंगल चार्ज में दो घंटे से अधिक का बैकअप ड्रोन देता है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मानक स्तर की बैटरी का प्रयोग किया जाता है। कृषकों के लिए वास्तव में यह भविष्य में एक वरदान साबित होगा। फसलों में होने वाली बीमारियों की पहचान भी ड्रोन से संभव होगी।
एनएल मेहरा, सहायक कृषि यंत्री, जबलपुर

- मैंने शुरू से ही किसानों को आधुनिक संसाधनों के प्रयोग के लिए प्रेरित किया है। अभी भी कई नवाचार चल रहे हैं, जिसमे ड्रोन खास है। ड्रोन के माध्यम से ऊंचाई वाली फसलों पर आसानी से एवं समान रूप से छिड़काव संभव है। ड्रोन में प्रयोग होने वाली दवा में 30 प्रतिशत तक की बचत होती है।
वीवी मौर्या, उपयंत्री कृषि अभियांत्रिकी जबलपुर

- ड्रोन या हल्के विमानों का प्रयोग खेती किसानी में नया है। मजदूरों की अनुपलब्धता या अधिक मजदूरी से किसान समय पर फसलों पर दवा का छिड़काव नहीं कर पाते हैं। ऐसे में ड्रोन का उपयोग बढ़ाने के लिए कृषि विभाग तत्परता से काम कर रहा है। आने वाले समय में अच्छी संभावनाएं हैं।
-रजनीश दुबे, कृषि विस्तार अधिकारी

- खेती में ड्रोन के उपयोग को लेकर दो वर्षों से जबलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि में कार्य चल रहा है। प्रदेश में पहली बार किसानों को ड्रोन अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। मप्र में अन्य प्रदेशों की तुलना में कम दर पर ड्रोन पायलट लाइसेंस की व्यवस्था भी की है।
इंजी. राजीव चौधरी, कृषि अभियांत्रिकी विभाग

बसामन मामा गौ वन्य-विहार गाय को आश्रय के साथ रोजगार के अवसर देगा

भोपाल। जागत गांव हमार

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बसामन मामा गौ वन्य-विहार अभ्यारण्य रीवा में आयोजित बैठक में वन्य-विहार के विकास कार्यों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बसामन मामा गौ वन्य-विहार प्रोजेक्ट प्रदेश में अपनी तरह की अनूठी परियोजना है। यह परियोजना निराश्रित गौवंश को आश्रय देने के क्षेत्र पूरे देश में आदर्श बनेगी। उन्होंने कहा कि गौ वन्य-विहार में गौवंश को आश्रय देने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। इसे गोबर गैस और सोलर प्लांट के माध्यम से ग्रीन एनर्जी का सेंटर बनाएंगे और यह आय का अतिरिक्त साधन भी बनेंगे।

गौ-सेवकों का मानदेय एक हजार रुपए बढ़ाने के निर्देश- उप मुख्यमंत्री ने वन्य विहार में कार्यरत गौ-सेवकों का मानदेय एक हजार रुपए बढ़ाने के निर्देश दिए। उप-मुख्यमंत्री ने पेयजल व्यवस्था, सौर ऊर्जा प्लांट तथा गौशाला के प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य को एक माह में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गौशाला के गोबर से कंप्रेस्ड गोबर गैस बनाकर नगर निगम को सप्लाई करें। इससे नगर निगम के वाहन चलाए जाएंगे। गौशाला के सभी शेडों में सोलर सिस्टम से सौर ऊर्जा का उत्पादन कराने के निर्देश दिए। साथ ही गोबर से गुणकारी खाद, गोनाइल तथा अन्य उत्पाद बनाने के लिए निर्देशित किया। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि इससे गौशाला से जुड़े स्वसहायता समूहों को स्वरोजगार के अवसर के साथ गौशाला को अतिरिक्त आय भी होगी। उन्होंने ने गौमाता की पूजा कर गौ-ग्रास खिलाया साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान में पौधे-रोपण किया। कमिश्नर बीएस जामोद, आईजी एमएस सिकरवार सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बीबीएफ बुवाई विधिः बुंदेलखंड के किसानों के लिए फायदेमंद

» डॉ. आरके प्रजापति
(वैज्ञानिक) कृषि विज्ञानं केंद्र, टीकमगढ़ (मप्र)

जलवायु परिवर्तन के दौर में बुंदेलखंड में खेती करना एक जोखिम और मुश्किलों भरा कार्य होता जा रहा है। यहां अधिकांशतः खरीफके मौसम में खेती का 90प्रतिशत भाग 22 जून से 30 सितंबर तक होने वाली वर्षा पर निर्भर करता है, लेकिन पिछले 10- वर्षों में वैश्विक स्तर पर हो रहे जलवायु परिवर्तन से बुंदेलखंड की जलवायु में भी बड़े बदलाव के परिणाम से खेती में नवाचार की आवश्यकता हो रही है।

कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के वैज्ञानिकों द्वारा विगत 10-वर्षों से जलवायु समुथानसील कृषि में राष्ट्रीय नवाचार परियोजना अंतर्गत ग्राम-काँटी, नंदनपुर, हसपुरा और कोड़िया में सैकड़ो किसानों के खेतों में चौड़ी-क्यारी-नाली व मेड-नाली जैसे बुवाई की विधियों से खरीफफसलों की बुवाई करवाई है। इसके अच्छे परिणाम मिले हैं। इस विधि से प्रचलित चौड़ी-क्यारी नाली विधि/मेड नाली पद्धति से बुवाई की जाती है। इसमें एक चौड़ी क्यारी में 3-4 कतारें होती है और क्यारी के दोनों तरफनालियां होती है। प्रत्येक दो कतारों के बीच लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर की लाइन से लाइन की दूरी फसल अनुसार रहती है। और 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी नाली दोनों क्यारी के किनारों में रहती है। क्यारी उठी हुई जमीन से 15-30 सेमी रहती है, जिससे फसल की कतारें मेड़ पर आ जाती हैं और गहरी नाली का उपयोग वर्षा जल में कम वर्षा की स्थिति में नाली का अंतिम छोर बंद करने से पानी रोकने में सहायक हो सकता है। इससे फसल में अधिक समय तक नमी बनी रहती है। वहीं अधिक वर्षा की स्थिति में नाली के अंतिम छोर को खोल देने से पर आवश्यकता से अधिक पानी खेतों से बाहर निकल जाता है और जल भराव से फसल सड़ने का खतरा कम हो जाता है। इससे फसलों को सही मात्रा में ऑक्सीजन तत्व व नाइट्रोजन उपलब्ध होती रहती है।

रबी के मौसम में यह जल संरक्षण करके सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। मेड़ बनने से खर्च और समय की बचत हो जाती है। सीजन से बोई गई फसलों के पौधों से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी निश्चित होने से प्रत्येक पौधे को पर्याप्त जगह वृद्धि के लिए पर्याप्त खाद एवं उर्वरक बराबर मात्रा में मिलती है। खेत में पौधों में एक समान वृद्धि आकार एवं उपज प्राप्त होती है। हवा, पानी का संचार पौधों और जड़ों को सही अनुपात में होता है। कृषि कार्य जैसे, नींदा नियंत्रण में नींदा नासक को छिड़काव करने में आसानी रहती है। मशीनों में दवाई के छिड़काव को आसानी से दूरी को घटाया-बढ़ाया जा सकता है। फसलों के अनुसार इस प्रकार की बुवाई पद्धति को अपनाकर उपज में 25 से 50प्रतिशत तक आवश्यकता में बढ़ोतरी की जा सकती है। किसानों को अधिक लाभ के लिए खरीफ फसलों सोयाबीन और तिल या मूंगफली की बुवाई मानसून आने के बाद जून में लगभग 100 मिमी वर्षा होने के बाद खेत में बुवाई की स्थितियां रहते हुए जुलाई के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में कर लें देना चाहिए। इस प्रकार की बुवाई मशीनों के जो कतार में चौड़ी क्यारी-नाली में करते हैं, यन्त्र उनको रिजल्ट प्लांटर, ब्रॉड बैंड फरो, रेस्ट बेड फरो आदि जैसे नाम से जाना जाता है। इनको अपनाने में जो समस्याएं हैं, उनमें किसानों के खेतों के आकार का छोटा होना या लघु सीमांत किसको की संख्या ज्यादा होना। छोटे जोत वाले किसान अपनी छिड़काव विधि को नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि इतनी छोटी जोत के लिए मशीन और ट्रैक्टर नहीं खरीदना चाहते हैं। कृषि यंत्रों का प्रबंधन, कृषि यंत्रों का उपयोग, रख रखाव। इस प्रकार की मशीनों का स्थानीय स्तर पर उपलब्ध न होना और इनका उपयोग का प्रशिक्षण या जानकारी रखरखाव करने का अभाव तथा कस्टम हायरिंग सेंटरों का काम होना।

बुवाई की आधुनिक विधि: चौड़ी क्यारी और नाली बुवाई

विधि (ब्रॉड बेड और फरो सिस्टम-बीबीएफ): चौड़ी क्यारी और नाली बुवाई विधि को मुख्य रूप से भारत में अर्द्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए (अर्द्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद) में विकसित किया गया था। पहले इस विधि का उपयोग इस मुख्य रूप से गहरी वर्टिसोल (गहरी काली चिकनी मिट्टी या भारी काली मिट्टी वाली मिट्टी जिसे कभी-कभी कपास की मिट्टी भी कहा जाता है) पर किया जाता था। यह मिट्टी की सतह को क्यारीयों में बदल के नियंत्रित नालियों द्वारा सतही जल निकासी को प्रोत्साहित करने की बहुत पुरानी अवधारणा का एक आधुनिक बुवाई तकनीक विधि है। ब्रिटेन में मध्यकालीन समय में इसका उपयोग चारागाहों को बेहतर बनाने के लिए किया जाता था और इसे रिग एंड फरो कहा जाता था। इस प्रणाली में लगभग 100 सेमी चौड़ी-चौड़ी क्यारियाँ होती हैं, जो लगभग 50 सेमी चौड़ी धँसी हुई नालियों (कुंडों) से अलग होती हैं। काली मिटटी पर कुंडों के साथ औसत ढलान 0.4 से 0.8 प्रतिशत होता है। चौड़ी क्यारी पर फसल की दो, तीन या चार पंक्तियाँ उगाई जा सकती हैं। क्यारी की चौड़ाई और फसल की ज्यामिति को खेती और सीड ड्रिल बुवाई यन्त्र के अनुरूप बदला जा सकता है। भारत में विकसित बीबी सीड ड्रिल मशीनों को ट्रेक्टर या बैलों बैल द्वारा खींचे जाने वाले पहिएदार यन्त्र बनाये जाते हैं। यह बुवाई विधि विशेष रूप से वर्टिसोल मिटटी के लिए उपयुक्त है।

बीबीएफबुवाई विधि का उद्देश्य: 1. मिट्टी की प्रोफाइल में नमी के संरक्षण को बढ़ावा देना। गहरे वर्टिसोल में 250 मिमी तक मिट्टी की नमी का संरक्षण हो सकता है, जो सूखे (ड्राई स्पेल) के मध्य-मौसम (मिड-सीजन) या देर-मौसम (लेट मानसून) के दौर में पौधों को सहारा देने के लिए पर्याप्त है। अंतर-फसल के माध्यम से दोहरी फसल की संभावना भी बढ़ जाती है। मिट्टी की बड़ी जल संरक्षण क्षमता बाद के शुष्क, लेकिन ठंडे बरसात के मौसम के दौरान विकास को अधिक आसानी से सहारा देती है।

2. अतिरिक्त वर्षा जल सतही अपवाह को बिना भूमि कटाव के सुरक्षित तरीके से खेत से बाहर निकलना.

3. क्यारियों में बेहतर जल निकासी वाली और अधिक आसानी से खेती की जाने वाली मिट्टी प्रदान करना।

4. छोटे टैंकों में संग्रहित अपवाह के पुनः उपयोग की संभावना। जीवन रक्षक सिंचाई की छोटी मात्रा का प्रयोग बारिश के दौरान सूखे की स्थिति में बहुत प्रभावी हो सकता है। विशेष रूप से गहरी वर्टिसोल की तुलना में कम भंडारण क्षमता वाली मिट्टी पर।

5. इस प्रणाली का एक महत्वपूर्ण बीबीएफसीड ड्रिल ट्रैक्टर द्वारा किया जाता है। सिंचाई जल का प्रबंधन सरल और अधिक कुशल है। औसतन फ्लैट बेड विधि (छिडकाव विधि) की तुलना में लगभग 30प्रतिशत कम सिंचाई जल की आवश्यकता होती है और फसल की पैदावार में 20प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होती है।

बीबीएफ रोपण विधि का लाभ: सब्जी की खेती में जल उपयोग दक्षता में वृद्धि। फसल उत्पादकता में वृद्धि। गैर-बरसात के दिनों में नमी का तनाव कम होता है। सिंचाई में समय की बचत। 20-25प्रतिशत कम बीज दर की आवश्यकता। 25-30प्रतिशत तक पानी की बचत। बेहतर खरपतवार प्रबंधन। फसल गिरने की समस्या कम होती है। सिंचाई के पानी में 25-50प्रतिशत तक की बचत। फसल की स्थिति में 70-75प्रतिशत सुधार। सिंचाई में समय की बचत (25-30प्रतिशत) (1.5 घंटा/हेक्टेयर/सिंचाई)। 20-25प्रतिशत कम बीज दर की आवश्यकता। पानी की बचत 25-30प्रतिशत तक। बेहतर फसल प्रबंधन। टमाटर की फसल में 10-15प्रतिशत अधिक उपज।

मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर (टोर-टोर)

» डॉ. महेंद्र सिंह
» डॉ. माधुरी शर्मा
» डॉ. उत्तम कुमार सरकार
– मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, नादेपचिविवि, जबलपुर, मध्य प्रदेश
– आईसीएआर- राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

महासीर को भारत की उत्कृष्ट खेल और खाद्य मछली के रूप में जाना जाता है, जो कि मप्र की जीवनरेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी में प्रमुख रूप से पाई जाती है। महासीर मछली क्रिस्टल साफ़मीठे पानी और उच्च ऑक्सीजन के साथ तेज़ बहने वाली चट्टानी धाराओं को पसंद करती है। महासीर की भोजन प्रकृति सर्वाहारी है और मांसाहारी से सर्वाहारी में अपने भोजन की आदत को बदल देती है। लिंग अलग-अलग होते हैं। निषेचन बाहरी होता है, मादा गहरे चट्टानी तालाबों में अंडे देती है और नर झुंड में मिल्ट्स छोड़ता है।

महासीर (टोर टोर) मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। महसीर उत्तर और उत्तर-पूर्वी भारत की अत्यंत बेशकीमती और प्रतिष्ठित मछलियों में से एक है, यह भारत में गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, राप्ती, शारदा, रामगंगा, कोसी, सोन, रिहंद, चंबल,केन, बेतवा, महानदी, नमज्दा, ताप्ती, माही, ब्रह्मपुत्र-बराक नदी प्रणाली, सिंधु, सतलुज और व्यास नदी सहित उप-हिमालयी श्रृंखला के साथ कई प्रमुख नदियों में मिलती है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग), असम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तरांचल राज्यों में फैली हुई है। यह प्रजाति नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन में भी पाई जाती है

महीसर की प्रजातियां: दुनिया में महासीर की 47 प्रजातियाँ हैं, जिनमें से भारत में 15 प्रजातियाँ हैं। महासीर की प्रजाति टोर, टॉर महासीर (टोर टोर); गोल्डन महासीर (टी. पुटिटोरा), डेक्कन महासीर (टी. खुद्री), हंपबैक महासीर (टी. मुसुल्लाह), मोसल महासीर (टी. मोसल), टी. नेली, टी. प्रोजेनीज़, टी. रेमादेवी, टी. कुलकर्णी, चॉकलेट महासीर (नियोलिसोचेलस हेक्सागोनोलेपिस) पाई जाती है।

संख्या में कमी के कारण: विभिन्न मानवजनित गतिविधियों ने देश भर में महसीर की आबादी पर बुरा असर डाला है। पिछले सौ वर्षों के दौरान पश्चिमी घाटों में व्यापक वनों की कटाई इसके पतन का एक प्रमुख कारण है। मछली प्रजातियों में गिरावट के प्रमुख कारणों में जलीय प्रणालियों की पारिस्थितिक स्थितियों का ह्रास, बांधों का निर्माण, ब्रूडफिश और किशोर मछलियों का अंधाधुंध शिकार, नदी घाटी परियोजनाएँ, औद्योगिक और मानवजनित हस्तक्षेप, विस्फोटकों, ज़हर और बिजली के झटके का उपयोग, विदेशी मछलियों की प्रजातियों का प्राकृतिक वातावरण मेंआनाशामिल हैं। दो प्राकृतिक बाधाएं जैसे विलंबित (देर से) परिपक्वता, कम प्रजनन क्षमता एवं, 24-28 डिग्री सेल्सियस पर 60-80 घंटे की लंबी हैचिंग अवधि और धीमी विकास दर और अत्यधिक शिकार (दोहन)वइस प्रजाति की संख्या में कमी के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक हैं । महाशीर में प्रजनन जून-अगस्त में माह होता है, इस अवधि के दौरान मछुआरे बड़ी मछलियों (ब्रूडर) को पकड़ने के लिए पाहू जाल (एक प्रकार का बैरिकेड) लगाते हैं, जब मछलियां प्रजनन के लिए चलती हैं तो वे जाल में फंस जाती हैं और अंडे छोड़ने और प्रजनन से पहले मर जाती हैं। यह नर्मदा नदी में महाशीर की संख्या में कमी के प्रमुख कारणों में से एक है।

संरक्षण के लिए उपाय: महाशीर का संरक्षण आवश्यक है और भारत में इसके संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। नदियों में लुप्तप्राय मछलियों के संरक्षण मुख्य चिंता के कारकों की पहचान की गई, जिसमें प्रमुख बीज एवं पूरक आहार की कमी और इसकी धीमी वृद्धि के कारण महाशीर कल्चर जलीय कृषि विदों के बीच लोकप्रिय नहीं है। बड़े पैमाने पर बीज उत्पादन और उचित तकनीकों के साथ फीड निर्माण का उपयोग महाशीर की घटती जनसंख्या की समस्या से निपटने में सहायक हो सकता है। इस बहुमूल्य मछली के संरक्षण और सुरक्षा के लिए राज्य सरकार और मध्य प्रदेश मत्स्य संघ द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। होशंगाबाद के पास डोंगरवाड़ा घाट और बरगी के पास टेमर नदी (नर्मदा नदी की सहायक नदी) मध्य प्रदेश के दो ऐसे स्थान हैं जहाँ टोर टोर के बीज अच्छी मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। भोपाल में कोलार बांध में मध्य प्रदेश के अन्य बांधों की तुलना में टोरटोर की अच्छी संख्या है, जो कि अधिक गहराई और बजरी के तल के कारण प्रजनन और इनके अस्तित्व के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करता है। आनुवंशिक विविधता का संरक्षण न केवल स्थायी मत्स्य पालन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह राष्ट्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न आणविक मार्कर्स का उपयोग करके उचित वर्गीकरण एवं पहचान लुप्तप्राय महसीर के संरक्षण की दिशा में एक आवश्यक कदम है। इन-सीटू संरक्षण और जीन बैंकिंग भी महसीर प्रजातियों के संरक्षण के लिए सबसे अच्छे माध्यम के रूप में काम कर सकते हैं। जलीय जर्मप्लाज्म संसाधनों का संरक्षण वैज्ञानिक प्रयास का एक महत्वपूर्णज क्षेत्र है और एन.बी.एफजी.आर., लखनऊ मछली जमज्प्लाज्म के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। टोरटोर के जर्मप्लाज्म को ब्रूड स्टॉक सुविधा की स्थापना और बीज उत्पादन के लिए विशेष हैचरी विकसित करके बढ़ाया और संरक्षित किया जा सकता है।

फसलों की बीमारी की वजह से तीन साल में दोगुनी हुई खाद्य-महंगाई

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 का मानना है कि खाद्य वस्तुओं की ऊंची महंगाई दर के लिए जलवायु परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण कारक बनकर उभरा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परंपरा के अनुकूल केंद्रीय बजट प्रस्तावित होने से एक दिन पहले 22 जुलाई को संसद में आथिज्क सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। सर्वेक्षण के मुताबिक, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति पिछले तीन सालों में लगभग दोगुनी हो गई है। सीएफपीआई वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2022 में 3.8 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 6.6 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2024 में 7.5 प्रतिशत हो गया।

सर्वेक्षण में खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण मौसम की प्रतिकूल स्थितियों को बताया गया है। इसमें कहा गया - शोध संकेत करते हैं कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण जलवायु परिवर्तन, लू , मानसून का असमान वितरण, बिना मौसम की बारिश, ओलावृष्टि, मूसलाधार बारिश और ऐतिहासिक शुष्क स्थितियां हैं। सर्वेक्षण में हाल की ऊंची खाद्य महंगाई को एक वैश्विक परिघटना बताया गया है। इसके मुताबिक, वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024 में कृषि-क्षेत्र चरम मौसम की घटनाओं, जलाशयों के निम्न स्तर और फसलों के खराब होने से प्रभावित हुआ, जिससे कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सब्जियां और दालें दो ऐसे मुख्य खाद्य पदार्थ हैं, जिनकी किसी परिवार के खाद्य बजट को तय करने में सबसे ज्यादा भागेदारी होती है। इन दोनों पर ही मौसम की अस्थिर स्थितियों का सबसे ज्यादा असर पड़ा। सर्वेक्षण में प्रतिकूल मौसम यानी जलवायु परिवर्तन और समग्र खाद्य मुद्रास्फीति के बीच संबंध बनाने के लिए कुछ विशिष्ट सब्जियों में अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि की व्याख्या की गई है। सर्वेक्षण के मुताबिक, जुलाई 2023 में टमाटर के दामों में वृद्धि का कारण फसल के उत्पादन के दौरान मौसम में बदलाव, क्षेत्र-विशेष के हिसाब से फसल में बीमारी जैसे - सफेद मक्खी (व्हाइट फ्लाई) का प्रकोप और देश के उत्तरी हिस्से में मानसून की बारिश का जल्दी आगमन था। प्याज के दामों में वृद्धि के लिए भी सर्वेक्षण में मौसम की स्थितियों को ही जिम्मेदार बताया गया है। इसके मुताबिक, प्याज के दामों में वृद्धि के कई कारण थे, जैसे - सिंचाई के अंतिम सीजन के दौरान बारिश होने की वजह से रबी में होने वाले प्याज की गुणवत्ता पर असर पड़ना, खरीफ की फसल के दौरान बुआई में देरी होना, इसी दौरान लंबे शुष्क मौसम का होना और दूसरे देशों से व्यापार संबंधी कारकों का असर डालना आदि। सर्वेक्षण के मुताबिक, पिछले दो सालों में अस्थिर और चरम मौसमी घटनाओं की वजहों से फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है।

सरकारी योजनाओं की गिरदावरी यानी सर्वे का काम कराया जाएगा

गांव के युवा करेंगे फसलों की गिरदावरी

भोपाल। जागत गांव हमार

सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में किसानों सहित युवाओं को नई-नई योजनाओं से जोड़कर लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से सरकारी योजनाओं की गिरदावरी यानी सर्वे का काम कराया जाएगा। राज्य सरकार की इस पहल से ग्रामीण युवाओं को गांव में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। राज्य सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद सहित बहुत सी सरकारी योजनाओं में फसलों की गिरदावरी की जाती है। इस काम के लिए अब राज्य सरकार ग्रामीण युवाओं को जोड़ना चाहती है, ताकि फसलों की सही गिरावदरी हो सके और योजना में और पारदर्शिता आए ताकि किसानों को इसका पूरा लाभ मिल सके। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशानुसार फसलों की गिरदावरी के लिए अब युवाओं को भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए इच्छुक युवाओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जो भी पढ़े-लिखे युवा इस काम को करना चाहते हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फसलों की मध्यप्रदेश भू अभिलेख नियमावली के मुताबिक फसल गिरदावरी का काम साल में तीन बार किया जाता है। पहला खरीफ फसल सीजन में, दूसरा जायद फसल सीजन में और तीसरा रबी फसल सीजन में। इस काम को सारा (स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन) एप के जरिये किया जाता है। इस गिरदावरी या सर्वे का उपयोग उपार्जन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि योजनाओं में सतत रूप से किया जाता है।

अभी तक यह काम कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा खेत में जाकर किया जाता रहा है। फसल गिरदावरी के काम में पारदर्शिता लाने के लिए भारत सरकार की ओर से डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य प्रारंभ किया गया है। यह प्रत्येक मौसम के लिए करीब 45 दिन की कार्यवाही होती है। इसमें जिओ फेंस (पार्सल लेवल) तकनीक के जरिये खेत में बोई गई फसल का फोटो खींचकर फसल सर्वेक्षण का काम नियत अंतराल में पूरा किया जाएगा। इस योजना के तहत खरीफ सीजन 2024 डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण के लिए सर्वेयर पंजीयन किया जाना है।

गांव के युवाओं का होगा चयन

खेतों के रिकॉर्ड ऑनलाइन करने के लिए युवाओं को प्रति खसरा आठ रुपए दिए जाएंगे। नई व्यवस्था के तहत गांव के कुछ युवाओं को ही पटवारी की जगह खेतों की गिरदावरी कराने के लिए चयनित किया जाएगा। चयनित युवक ही मोबाइल एप की मदद से गिरदावरी का काम पूरा करेंगे। इससे किसानों की फसल का सही रिकॉर्ड किसान चढ़वा सकेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए फर्जी जानकारी भी नहीं दे पाएंगे। इस काम को नीमच और सिवनी जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वर्ष 2023 में शामिल किया गया था। यहां सफलता मिलने पर प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसे लागू किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत सभी 52 जिलों के 53 हजार गांवों के करीब 80 लाख किसानों के खेतों में होने वाली फसलों का रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा। इसको लेकर आयुक्त भू-अभिलेख ने सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र भी जारी कर दिए हैं। यह होती है गिरदावरी किसानों को सरकार की योजनाओं से जोडने के लिए उनके खेत का रकबा और होने वाली फसल को आधार बनाया जाता है। इसके लिए हर खेत की गिरदावरी होती है। इसमें देखा जाता है कि किस खेत में कौन सी फसल लगाई गई है। रबी, खरीफ और अन्य सीजन में क्या फसल ली गई है इसकी भी सटीक जानकारी इससे मिलेगी। फसल की गिरदावरी साल में तीन बार सारा एप के माध्यम से की जाएगी।

युवाओं को जुलाई में दिया गया प्रशिक्षण

सर्वेयर बनने के लिए इच्छुक युवाओं को 10 जुलाई तक पंजीयन करवाया गया। इसके लिए, अनिवार्य योग्यता रखी गई थी, उसी गांव का स्थानीय निवासी होना है, जहां वे सर्वे करना चाहते हैं। आवेदक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही उनके पास एंड्राइड 6 वर्जन या इससे अधिक वर्जन का फोन हो। पंजीयन के बाद युवाओं को 25 जुलाई तक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षित युवा अगस्त से 15 सितंबर तक गांव में खसरा के हिसाब से गिरदावरी करेंगे। इसके बाद पर्यवेक्षक गिरदावरी का सत्यापन करेंगे। इसके बाद किसानों को दावा-आपत्ति के लिए समय दिया जाएगा। उसके बाद निराकरण होगा। इसके बाद वैरीफायर का अनुमोदन और अंतिम अनुमोदन की प्रकिया पूरी होगी। पंजीयन और योजना संबंधी अन्य जानकारी के लिए सारा एप पर जाएं। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का कहना है कि यह योजना गिरदावरी के काम में पारदर्शिता लाएगी। स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही उन्हें अनुभव भी मिलेगा। योजना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी हो गई है।

न तो राशि खर्च की गई और न ही सरकार को लौटाई

पंचायतों के अरबों रुपए पर विभाग ने मारी कुंडली, रुक गया विकास का रथ

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश सरकार का पंचायत विभाग अरबों रुपए के बजट पर कुंडली मारे बैठा रहा। इससे न तो वह राशि विकास के कामों पर खर्च की गई है और न ही वित्त वर्ष की समाप्ती पर उस राशि को सरकार को ही लौटाया गया है। यह खुलासा हुआ है हाल ही में विधानसभा में पेश की गई कैग की रिपोर्ट में। अहम बात यह है कि विभाग ने उन योजनाओं में भी गंभीर लापरवाही दिखाई है, जो न केवल केंद्र की प्राथमिकता वाली योजनाएं हैं, बल्कि राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में भी शामिल हैं। इसमें वह योजना भी शामिल है, जिस प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लेकर प्रदेश सरकार देश में सबसे अच्छा काम होने का दावा कर खुद की पीठ थपथपाती है। रिपोर्ट में इसकी सच्चाई भी बताई गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च 2023 तक पीएम ग्रामीण आवास योजना का 171.43 करोड़ खर्च नहीं किया गया है। वहीं पंच परमेश्वर योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना सहित स्वच्छ भारत मिशन का करीब 896 करोड़ बैंक में पड़ा है। पंचायत विभाग ने इसे न तो सरकार को लौटाया है और न ही खर्च किया है।

खाते में 456.12 करोड़ जमा

पंचायत राज संचालनालय ने राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के नाम पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की भोपाल शाखा में एक खाता क्रमांक-3245631964 खोला था। वित्त विभाग की कार्योत्तर स्वीकृति के बाद यह खाता इस शर्त पर खोला गया कि द्वितीय अनुपूरक में बजट का प्रावधान कर इस योजना को बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इसके तहत सभी जिला पंचायत एवं जनपद सीईओ को 29 जून 2020 तक उक्त खाते में राशि जमा करने के निर्देश दिए गए। जिससे बैंक खाते में 456.12 करोड़ जमा हो गए।

जमा राशि में 22 लाख का अंतर

अन्य बैंक खातों में पड़ी राशि 440.78 करोड़ भी इस खाते में अंतरित कर दी गई। इससे बैंक एकाउंट में 896.68 करोड़ जमा हो गया। 31 मार्च 2023 को बैंक स्टेटमेंट में 896.68 करोड़ दिखाया गया, जबकि पंचायत संचालनालय के अभिलेखों में राशि 896.20 करोड़ जमा होना बताई गई। यानी 22 लाख का अंतर इसमें ही पाया गया।

इन योजनाओं का पैसा भी नहीं किया खर्च

विभाग ने एनआईसी रिफंड का 83 लाख, पेसा अधिनियम का 15 लाख, सांसद आदर्श ग्राम योजना का 23 लाख, प्रदर्शन अनुदान का 20 लाख, 12वीं वित्त आयोग का 58 लाख, मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना का 23 लाख शामिल है। इस तरह विभिन्न योजनाओं में पैसा होने के बाद भी पंचायत राज संचालनालय द्वारा खर्च नहीं किया गया। यहां तक अगस्त 2023 तक उक्त राशि वित्त विभाग को नहीं लौटाई गई थी।

मुरैना | बिक्री और स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध

जांच में अमानक निकला बीज

मुरैना। जागत गांव मार

मुरैना जिले में अमानक खाद-बीज की खपत पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। रवी हो या खरीफ का सीजन, जब भी बोवनी का समय होता है, बाजार में नकली व अमानक खाद-बीज खपने लगता है। बीते सीजन में भी ऐसे कई मामले सामने आए। कृषि विभाग ने इस सीजन में स्पेलिंग शुरू की तो फिर अमानक बीच बाजार में बिकने के मामले सामने आए हैं। जांच में फेल होने पर कृषि विभाग ने तीन फर्मों के बीच की विक्री, भंडारण व परिवहन पर प्रतिबंध लगाया है। बीज अनुज्ञापन पंजीयन अधिकारी एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक पीसी पटेल ने बताया, कि बीते दिनों कोर्टेवा एग्री साइंस सीड्स प्रालि तेलंगाना की कंपनी के बीच के संपल सबलगढ़ कस्बे की दुकान मैसर्स मंगल बीज भंडार से लिए थे। लैब में हुई जांच में यह बीज अमानक पाया गया है। इसके अलावा कोहिनूर हाइब्रिड सीड्स निजामाबाद का बीज मैसर्स शिवा बीज भंडार जीवाजीगंज मुरैना से विक्रय किया जा रहा था।

सेंपल मिले अमानक

इस बीज के भी सेंपल लिए गए, जो जांच में अमानक पाए गए हैं। इसी तरह मुरैना शहर के जीवाजीगंज में मैसर्स अग्रवाल सीड्स स्टोर से कार्तिक वायोसीड्स सावरकांटा गुजरात की कंपनी के बीज के सेंपल लिए, यह भी जांच में फेल हो गए। उप संचालक पीसी पटेल ने बताया, कि जांच में फेल हुए बीजों के पूरी लाट पर प्रतिबंध लगाया गया है।

खाद के लिए कतार

हर बार की तरह इस बार भी जिला प्रशासन दावा कर रहा है, कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं हैं। फिर भी हालत यह है कि मुरैना जिला मुख्यालय से लेकर कस्बाई क्षेत्र जहां-जहां खाद का वितरण किया जा रहा है, वहां खाद के लिए किसानों की कतार लग रही है।

आधार देख दे रहे खाद

जौरा कस्बे में खाद के लिए कतार में लगे किसानों का नंबर पांच-पांच घंटे में आ पा रहा है। मुरैना में पुलिस की निगरानी में खाद का वितरण हो रहा है। किसान का आधार कार्ड दिखाने पर पांच बोरे यूरिया दिया जा रहा है, जिस किसान को 10 बोरे खाद की जरूरत है, उस किसान के परिवार के दो सदस्य आधार कार्ड लेकर खाद की लाइन में लग रहे हैं।

राजस्व अधिकारी नजर रखें

उधर, कलेक्टर अंकित अस्थाना ने एसडीएम-तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं, कि खाद वितरण पर राजस्व अधिकारी नजर रखें। जिले में पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा खाद है, किसानों को भरपूर खाद खाद की कमी नहीं है, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खाद अधिक मात्रा में उपलब्ध। वितरण की व्यवस्था को राजस्व अधिकारी संभाले, ताकि किसानों को आसानी से खाद मिल सके।

केवीके द्वारा 100 दिन विकसित भारत अभियान के तहत आयोजित प्रशिक्षण के दौरान डॉ. एसपी सिंह ने कहा

मृदा स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए केंचुआ खाद का प्रयोग करें किसान

भिंड। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के तहत 100 दिन विकसित भारत अभियान के क्रम में विभिन्न तकनीकी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रशिक्षण का आयोजन कर किसानों को तकनीकी सलाह प्रदान की जा रही है। केंद्र द्वारा इस क्रम में अब तक तीन अलग-अलग विषयों पर पांच-पांच दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किए जा चुके हैं। 100 दिन कार्यक्रम अभियान के तहत 5 दिवसीय प्रशिक्षण की श्रृंखला में खरीफ फसलों की उत्पादन तकनीकी, बीज उत्पादन तकनीकी एवं केंचुआ खाद उत्पादन तकनीकी विषय पर गिरवासा, उद्योतपुरा एवं मलंड में प्रशिक्षकों का आयोजन कर किसान एवं युवाओं को तकनीकी जानकारी प्रदान की गई है।

तीन महीने में केंचुआ खाद बनकर तैयार

रौन क्षेत्र के मलंड गांव में प्रशिक्षण के दौरान किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एसपी सिंह ने कहा कि मृदा एवं मानव स्वास्थ्य के लिए खेतों में केंचुआ खाद का प्रयोग बहुत जरूरी है। केंचुआ खाद बनाने के लिए गोबर, फसलों का कचरा, पशुओं के नीचे की बिछावन, पेड़ पौधों की पत्तियां आदि के साथ केंचुओं की आवश्यकता होती है। केंचुआ खाद बनाने के लिए भारत में दो प्रजातियों के केंचुए प्रयोग किए जाते हैं। जिसमें प्रमुख रूप से केंचुए की विदेशी प्रजाति ऐस्टीनियां फोटीडा एवं भारतीय प्रजाति जय गोपाल प्रयोग की जा रही है। उन्होंने बताया कि लगभग तीन महीने में केंचुआ खाद बनकर तैयार हो जाती है। जिसका प्रयोग खेतों में सीधे रूप में किया जाता है।

केंचुआ खाद में फसलों के लिए सभी 16 पोषक तत्व

केंचुआ खाद में फसलों के लिए आवश्यक सभी 16 पोषक तत्व पाए जाते हैं। डॉ सिंह ने बताया कि इसके प्रयोग से जमीन की उर्वरता में सुधार के साथ ही जीवाश्म में वृद्धि होती है। इस अवसर पर प्रशिक्षण में बोलते हुए मृदा विज्ञानी डॉ. बीपीएस रघुवंशी ने बताया कि खेतों में लगातार केंचुआ खाद प्रयोग करने से जमीन की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। इसके साथ ही ऐसे खेतों से पैदा होने वाले फल, सब्जियां, दलहन, तिलहन एवं खाद्यान्न स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहते हैं।

बढ़ जाएगा फसलों का उत्पादन

केंद्र के उद्यान वैज्ञानिक डॉ. करणवीर सिंह ने बताया कि केंचुआ खाद का उद्यानिकीय फसलों जैसे सब्जी एवं फल-फूल की खेती में प्रयोग करने पर अच्छा एवं गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त होता है। किसानों को फसल उत्पादन पर आने वाली लागत कम होती है। इसलिए किसानों को चाहिए को वह रासायनिक उर्वरकों के साथ ही मृदा के अच्छे स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता युक्त उत्पादन के लिए केंचुए खाद का प्रयोग अवश्य करें। प्रशिक्षण के दौरान में केंद्र के वैज्ञानिक डॉ.नरेंद्र सिंह भदोरिया, डॉ.रूपेंद्र कुमार, डॉ.आरपीएस तोमर एवं दीपेंद्र शर्मा द्वारा किसानों को अलग-अलग विषयों पर जानकारी प्रदान करने की गई।

पशुओं में फैसिओलोसिस रोग का खतरा

गगन बेडरे, पूजा दीक्षित, अमित साहू, बालेश्वरी दीक्षित एवं आलोक कुमार दीक्षित
पशु चिकित्सा एवं पशुपालन
महाविद्यालय, रीवा (मप्र)

यह मवेशियों में होने वाली बीमारी है, जो फैसिओला नाम के परजीवी से होती है। इस परजीवी की दो प्रजातियां होती हैं, पहला फैसिओला जाइजेंटिका और दूसरा फैसिओला हेपेटिका। हमारे देश में ज्यादातर संक्रमण फैसिओला जाइजेंटिका से होता है। मवेशियों में ये बीमारी घोंघों से फैलती है। यह बीमारी गाय, भैंस, भेड़ और बकरी में होती है। आमतौर पर यह बीमारी तालाब या पानी के स्त्रोत वाले इलाकों में ज्यादा पाई जाती है क्योंकि फैसिओला परजीवी अपना जीवन चक्र संपन्न करने के लिए घोंघों पर निर्भर होता है। यह बीमारी दो प्रकार की हो सकती है। 1. तीव्र. 2. जीर्ण।

तीव्र : यह प्रकार भेड़ में ज्यादा पाया जाता है। पशु की अचानक मृत्यु इस प्रकार की विशेषता है। आमतौर पर यह प्रकार गर्मी और शरद ऋतु में देखी जाती है। जिगर के नष्ट होने पर लीवर फेल होने के लक्षण दिखते हैं। इस प्रकार में वजन में कमी, पीली श्लेष्मा झिल्ली, देखने को मिलती है।

जीर्ण: यह प्रकार कई हफ्ते या महीने के बाद दिखता है। इस प्रकार में वज़न में कमी, दूध उत्पादन में कमी, खून की कमी और जबड़े की सूजन देखने को इस प्रकार में है।

रोगजनन: तीव्र प्रकार में, परजीवी जिगर को छलनी कर देता है जिससे जिगर के काम करने की शक्ति कम हो जाती है । वही जीर्ण रूप में विकसित परजीवी पित्त नलिका में पाये जाते हैं और अंडे देते हैं जो की पशु के मल के रास्ते से निकलते रहते हैं।

निदान: निदान के लिए बीमारी के लक्षण, चराई का इतिहास और मौसमी स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा पशु के मल में फैसिओला के अंडे पाये जाने से भी निदान हो सकता है जो कि बीमारी होने के 13 हफ्ते बाद ही मल में मिलते हैं। शव परीक्षण में जिगर का रूप मिट्टी के पाइप जैसा हो जाता है। एलिज़ा तकनीक का उपयोग करके इस बीमारी का निदान दो हफ्तों में किया जा सकता है।

नियंत्रण: इस बीमारी की रोकथाम तीन मुख्य कारकों पर आधारित है।

घोंघों का नियंत्रण : घोंघे को खत्म करने के लिए कॉपर सल्फेट का उपयोग बेहद कारगर साबित होता है। इसके अलावा डीसीपीएच तीन से पांच पीपीएम के उपयोग से भी घोंघे को नियंत्रित कर सकते हैं। जिन जगहों पर ज्यादा पानी एकट्ठा होता है या घोंघे रहते हैं वहां जानवरों को पानी पिलाने या चराने ना ले जाएं। तालाबों के आस पास बागड़ लगाकर भी पशुओं को रोका जा सकता है। इसके अलावा तालाबों में बतख या मेंढक पालकर भी घोंघों का नियंत्रण किया जा सकता है।

बीमार पशुओं का इलाज : बीमार पशुओं के इलाज के लिए निम्नलिखित दवाइयों का उपयोग किया जा सकता है।

ट्राईक्ल बेंडाजोल: यह दवाई फैसिओला के नवजात एवम व्यस्क सभी अवस्थाओं में कारगर है।

- भेड़ में 10 एमजी प्रति किलो पशु के वजन के हिसाब से।
- गाय में 12 एमजी प्रति किलो पशु के वजन के हिसाब से।

ऑक्सीक्लोजानाइड: गाय में 15 एमजी प्रति किलो पशु के वजन के हिसाब से विकसित परजीवी को मारने में सक्षम है।

एल्बेंडाजोल: गाय में 10 एमजी प्रति किलो पशु के वजन के हिसाब से विकसित परजीवी को मारने में सक्षम है जबकि भेड़ों में 7.5 एमजी प्रति किलो पशु के वजन के हिसाब से दिया जाता है।

नाइट्रॉक्सिनिल: इस दवाई को चमड़ी के नीचे इंजेक्शन के रूप में 10 एमजी प्रति किलो पशु के वजन के हिसाब से देने पर यह परजीवी को मारने में सक्षम है ।

क्लोसेंटल: 10 एमजी प्रति किलो पशु के वजन के हिसाब से दिया जाता है। इसके अलावा अगर जानवरों में खून की कमी है तो उसका उपचार भी करना चाहिये, जिसके लिए आयरन का इंजेक्शन या गोली दी जा सकती है। द्रव चिकित्सा दिया जा सकती है।

जंगली जानवरों की रोकथाम: जंगली या आवारा पशु संक्रमण के स्रोत का काम करते हैं, जिसके कारण पालतू जानवरों को संक्रमण का खतरा बना रहता है।

एफपीओ और किसानों के लिए वायदा बाजार पर जागरूकता एंव प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

सागर। एफपीओ और किसानों के लिए वायदा बाजार पर जागरूकता लाने गत दिवस एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र सागर में सेबी अन्तर्गत एनसीडीईएक्स. द्वारा कमोडिटी डेरीवेटीज पर जिले में कार्यरत एफपीओ के डायरेक्टर, सदस्यों, सचिवों आदि को जागरूकता एवं प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में देसी डिप्लोमा कर रहे प्रशिक्षणार्थियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन एनसीडीईएक्स. से पुरूषार्थ प्रताप सिंह ने मुख्य रूप से इस बात पर विस्तार से प्रकाश डाला कि किस प्रकार कृषि उत्पादकों को वायदा बाजार के तहत एनसीडीईएक्स के माध्यम से भाव लॉक किया जा सकता है। ताकि भाव जोखिम ना उठाना पड़े। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र, सागर के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. केएस यादव, डॉ. आषीष कुमार त्रिपाठी, डॉ. ममता सिंह, डॉ. वैशाली शर्मा ने उन्नत कृषि उत्पादन तकनीक, भण्डार गृह में जींस का रख-रखाव, उत्पाद की गुणवत्ता, ब्रांडिग एवं मार्केटिंग आदि पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया।

डेयरी इकाई में वर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना

रीवा । कृषि महाविद्यालय रीवा मप्र के पशुपालन विभाग में संचालित डेरी इकाई में वर्मी कंपोस्ट यूनिट मे विधिवत केंचुए का इनोक्यूलेशन किया गया। यह केंचुआ उत्पादन इकाई के स्थापित हो जाने से डेरी को अत्यंत लाभ मिलेगा। कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिक डॉ. ज्ञानी दत्त शर्मा, डॉ.राधा सिंह, डॉ. दिव्या सिंह, डॉ. गुफरान चत्रसाल पांडे, डॉ. एके गिरि एवं डॉ.संजय सिंह थे। डॉ.संजय सिंह का मार्गदर्शन एवं गिरी का प्रयास अत्यंत सराहनीय है। आशा है कि डेरी इकाई में वर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना हो जाने से कृषकों के लिए एक उच्च स्तरीय केंचुआ की खाद तैयार होगी, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा।

ठेकेदारी छोड़ शुरू की मौसंबी की खेती

सफलता देख तीन छोटे भाइयों ने भी लगाए पौधे,अब चारों को हो रही अच्छी कमाई

बिजली कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर रहे 75 साल के राजेंद्र यादव मौसंबी की खेती कर रहे हैं। 24 साल पहले एक बीघा में 100 पौधों से शुरुआत की। अब 14 बीघा में 1500 से ज्यादा पेड़ हो गए हैं। इससे हर साल करीब 12 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट भी हो रहा है। 10 से 12 लोगों को रोजगार भी दे रखा है। राजेंद्र सिंह मुरैना जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर चैना गांव में रहते हैं। जागत गांव हमार अपने इस अंक में राजेंद्र सिंह के बार में बता रहा है। उन्होंने मौसंबी की खेती से इलाके में अलग पहचान बनाई है। राजेंद्र की सफलता देख तीन छोटे भाइयों ने भी मौसंबी की खेती शुरू कर दी। इन्हें भी हर साल 4 से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है।

मुरैना। जागत गांव हमार

तीन दशक तक बिजली कंपनी में इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम किया। बिजली लाइनें डालना और सब स्टेशन बनाने का काम था। अब यह काम बेटा विनोद यादव कर रहा है। ठेकेदारी के दौरान इनकम तो अच्छी हो रही थी, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं थी। लग रहा था कि प्रकृति से दूर होता जा रहा हूं। फिर एक दिन कारोबार बेटे विनोद सिंह को सौंप दिया। मैंने मौसंबी की खेती करने की ठानी। साल 2000 में महाराष्ट्र से 100 पौधे लाकर एक बीघा जमीन में लगाए। तीन साल बाद पेड़ों में फल आने शुरू हो गए। पहले साल 80 हजार रुपए की मौसंबी बेची। अगले दो साल तक सवा-सवा लाख रुपए में फसल बेची। फायदा होने लगा, तो पौधों की संख्या बढ़ाता चला गया। आज 14 बीघा जमीन में 1500 से ज्यादा पेड़ हो गए हैं। इनमें कुछ नींबू के पेड़ भी हैं। पपीता, केला और अनार के भी पेड़ लगाए हैं। पिछले साल 15 लाख की फसल बेची थी। इसमें दो लाख रुपए नींबू के पेड़ों से आमदनी हुई थी।

बड़े भाई की सफलता देख तीन भाइयों ने भी शुरू की खेती- मैं चार भाइयों में बड़ा हूं। छोटे भाई मुरारीलाल यादव, दीनबंधु यादव और लक्ष्मीनारायण यादव हैं। जब मुझे मौसंबी की खेती में मुनाफा होने लगा, तो तीनों भाइयों ने भी मौसंबी की खेती शुरू कर दी। मुरारीलाल ने 5 बीघा, दीनबंधु ने 4 बीघा और लक्ष्मीनारायण ने 3-4 बीघा में मौसंबी उगाई है। पिछले साल तीनों भाइयों को 4 से 5 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। यही नहीं, पड़ोसी मुकेश यादव ने भी मौसंबी के पौधे लगाए हैं।

वन टाइम इन्वेस्टमेंट है मौसंबी की खेती

मौसंबी की खेती में मैंने एक बार 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। पौधे खरीदकर लाना, तार फेंसिंग कराना, गड्ढे खोदने के लिए मजदूरों को लगाने में पैसे खर्च हुए थे। इसके बाद दोबारा पैसे नहीं लगाने पड़े। अब हर साल अच्छा उत्पादन हो रहा है। खेती-किसानी और प्रकृति से जुड़े हैं, तो अच्छा लग रहा है।

एक पेड़ से 50 किलो तक मौसंबी

मौसंबी का पेड़ तीन साल बाद ही फल देना शुरू कर देता है। अच्छी फसल आने में 5 साल लग जाते हैं। एक पेड़ से 20 से 30 किलो तक मौसंबी निकलती हैं। एक से दो साल बाद पैदावार बढ़ जाती है। ऐसे में एक पेड़ से 50 किलो तक पैदावार मिल सकती है। बाजार में यह 40 से लेकर 70 रुपए/किलोग्राम तक बिक जाती है।

देखरेख में तीन लाख रुपए की आती है लागत

राजेन्द्र सिंह यादव ने अपने खेत में मकान भी बनवाया है। इसके बगल में ही एक 100 केवी का ट्रांसफार्मर भी लगवाया। वे बताते हैं कि पैतृक मकान गांव में है, लेकिन ज्यादातर समय यहीं बीतता है। खेतों में साफ-सफाई, खाद डालने, दवा छिड़काव के लिए महीने में 15 दिन 10 से 12 मजदूर काम करते हैं। इसके अलावा, दो लोग साल भर नियमित रूप से काम करते हैं। इसमें हर साल करीब तीन लाख की लागत आती है।

ऐसे लगाएं मौसंबी के पौधे

पहले मिट्टी की जुताई करके खेत तैयार कर लें। इसके बाद गोबर खाद डालकर रोटावेटर से जुताई करें। फिर पौधों की रोपाई के लिए गड्ढे तैयार कर लें। हर गड्ढे के बीच 7 से 8 फीट दूरी होनी चाहिए। पौधे लगाने के बाद पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। समय-समय पर खाद का छिड़काव और सिंचाई करते रहें। इल्ली का प्रकोप होने पर कोरोजोन कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा, यूरिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं।

गर्मी-सर्दी दोनों ही मौसमों में कर सकते हैं खेती

खास बात है कि मौसंबी की खेती गर्मी और सर्दी दोनों ही मौसम में कर सकते हैं। इसके लिए दोमट मिट्टी सही मानी जाती है, जिसमें उचित जल निकासी होनी चाहिए। इसके लिए मिट्टी 5.5 से 7.5 क्र॥ मान वाली होनी चाहिए। खेती से पहले कृषि वैज्ञानिकों से सलाह जरूर ले लें। मौसंबी के पौधों की रेगुलर अंतराल पर ड्रिप से सिंचाई करनी चाहिए। गर्मी में 5 से 10 दिन और सर्दियों में 10 से 15 दिन के समय-समय पर पानी देना चाहिए। बारिश में ध्यान रखें कि खेत में पानी ना भरे। मौसंबी के खेत में लगाए गए पौधों को स्थिर होने में 2 महीने का समय लग जाता है।

खेती के लिए खाद-उर्वरक

मौसंबी एक बहुवर्षीय बागवानी फसल है। इसके पौधों के उचित विकास और अच्छी उपज लेने के लिए आप इसमें समय समय पर खाद और उर्वरक का छिड़काव करें। पहले साल पौधे में आवश्यकतानुसार गोबर की खाद, नीम की खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश आदि का छिड़काव करें।

मुख्यमंत्री मोहन ने की उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की समीक्षा

उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण से किसान और उद्योगपति दोनों को मिलेगा लाभ

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों से किसान और उद्योगपति दोनों लाभान्वित होंगे। इनके माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में उद्यमिता और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अत: उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के परस्पर समन्वय से रोजगार के अवसरों व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस दिशा में सार्थक प्रयास किए गए हैं। किसानों के साथ उनके परिवारों को जोड़ने के लिए स्व-सहायता समूहों का भी गठन किया जाए। प्रदेश में संभाग स्तर पर हाईटेक नर्सरियां स्थापित कर आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।

उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग का बजट बढ़ाकर बाजार की माँग के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाएं। इस दिशा में हॉर्टिकल्चर प्रमोशन एजेंसी स्थापित कर समय-सीमा व रोडमैप निर्धारित करते हुए कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, मुख्य सचिव वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव वित्त मनीष सिंह, प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश के संतरा, केला, पान, लहसुन आदि की राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान के लिए हों प्रयास

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश मसालों के उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। अत: प्रदेश में मसालों की पृथक मंडी विकसित की जाए। साथ ही मसालों की खेती का अन्य जिलों में भी विस्तार किया जाए। प्रदेश में बड़े पैमाने पर फल, सब्जी, मसालों आदि का उत्पादन होता है। अत: मध्यप्रदेश के संतरा, केला, पान, लहसुन आदि की राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में जारी वृक्षारोपण अभियान में फलदार पौधे लगाने को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में फल, सब्जियों, औषधीय पौधों आदि के आर्गेनिक प्रोडक्शन, उनके डीहाइड्रेशन प्लांट व गामा रेडिएशन जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए गए।

बेहतर कार्य करने वालों को शासकीय कार्यक्रमों में सम्मानित किया जाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि किसान को उसकी मेहनत और निवेश का पूरा लाभ मिले व परिस्थितिवश किसी भी स्थिति में उन्हें नुकसान न उठाना पड़े। अत: आधुनिकतम तकनीक और शासकीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए जिला स्तर पर कार्यशाला आयोजित की जाएं। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वालों को शासकीय कार्य में सम्मानित किया जाए और उनकी उपलब्धियों को कार्य में प्रदर्शित करने के साथ उनसे संवाद स्थापित करने की भी व्यवस्था हो, जिससे अन्य किसान व उद्यमी प्रेरणा प्राप्त कर सकें। बैठक में उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में केन्द्र पोषित योजनाओं, राज्य पोषित योजनाओं, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरीगेशन योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना पर प्रदेश में जारी गतिविधियों पर प्रस्तुतिकरण दिया गया।

मुख्यमंत्री ने की खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा

प्रदेश में वितरित होने वाली राशन सामग्री में श्रीअन्न को शामिल किया जाए : यादव

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में वितरित होने वाली राशन सामग्री में प्रदेश में उत्पन्न होने वाले ज्वार, बाजरा, रागी जैसे श्रीअन्न को शामिल किया जाए। इसके लिए स्थानीय किसानों से अनाज लेने और प्रक्रिया में स्व-सहायता समूहों को जोड़ने पर विचार किया जाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जिन्हें पर्ची जारी की गई है। वह योजना के लिए पात्र हैं या नहीं इसका भी सर्वे कराया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। मंत्रालय में हुई बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, मुख्य सचिव वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा सहित अधिकारी उपस्थित थे।

राज्य स्तर पर गठित हो गैस कार्पोरेशन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नापतौल विभाग के अमले की यूनिफार्म तय की जाए। अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र, केरल, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना आदि में इस संबंध में जारी व्यवस्था के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने पाइप लाइन द्वारा रसोई गैस उपलब्ध कराने संबंधी गतिविधि के लिए राज्य स्तर पर गैस कार्पोरेशन गठित करने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में भी गैस उपयोग की संभावना है, अत: इसकी आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना बनाई जाए। अन्य राज्यों में इस संबंध में लागू व्यवस्था का भी अध्ययन किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए नीति बनाई जाए। साथ ही भू-जल भंडारण के संरक्षण और बिजली की बचत के दृष्टिगत बिना मौसम की धान व मूंग के उत्पादन को हतोत्साहित किया जाए। इसके लिए किसानों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से किसान सम्मेलन और कृषि विशेषज्ञों के साथ परिचर्चाएं भी की जाएं।

सा.वि.प्र. के सुदृढ़ीकरण तथा अन्य योजनाओं पर हुआ प्रस्तुतिकरण

बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फोर्टिफाईड चावल, शक्कर एवं नमक वितरण अनुसूचित जाति जनजाति विद्यार्थियों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने वन-नेशन-वन राशन कार्ड प्रधानमंत्री राशन आपके ग्राम योजना मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं को 450 रुपए में गैस रिफिल उपलब्ध करान प्रधानमंत्री जनमन मिशन गेहूं उपार्जन की स्थिति और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए जारी गतिविधियों पर प्रस्तुतिकरण के साथ चर्चा भी हुई।

डेयरी व्यवसाय अपनाकर छाया दीदी बन गई लखपति

भोपाल। खरगोन जिले की छाया यादव ने गरीबी को बहुत करीब से देखा है। उन्हें अच्छी तरह पता है कि अभावों के बीच रहकर कैसे जीवन गुजारा जाता है। लेकिन अब छाया यादव के दिन बदल गए हैं। छाया यादव ने मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर डेयरी व्यवसाय को अपना लिया है। इस व्यवसाय से उन्हें अब हर माह 20 हजार रुपये की शुद्ध आय हो रही है। छाया की इस सफलता ने उनका सामाजिक रूतबा भी बढ़ा दिया है। अब हर कोई उन्हें लखपति छाया दीदी के नाम से पहचानता है।

खरगोन जिले के भीकनगांव विकासखंड के ग्राम रेहगांव की छाया यादव के परिवार में 4 सदस्य हैं। परिवार के पास कम कृषि भूमि होने और रोजगार के साधन नहीं होने के कारण उनके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब छाया यादव आजीविका मिशन से जुड़ गई तो उनके दिन भी बदलने लगे। आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद उन्होंने अपने पति सुनील यादव के साथ पशु पालन का काम प्रारंभ किया। शुरुआत में उन्होंने कम दूध देने वाली भैंसों को कम कीमत में लेकर उन्हें अच्छी तरह से तैयार ऊंची कीमत में बेचना शुरू किया। इसके बाद छाया यादव ने बैंक से एक लाख रुपए का ऋण लेकर डेयरी का काम शुरू किया। इस काम में पूरे परिवार ने उनका साथ दिया। आज वह प्रतिदिन 30 से 40 लीटर दूध बेच रही है। इससे उन्हें प्रतिमाह 15 से 20 हजार रुपए तक की शुद्ध बचत होने लगी है।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)